



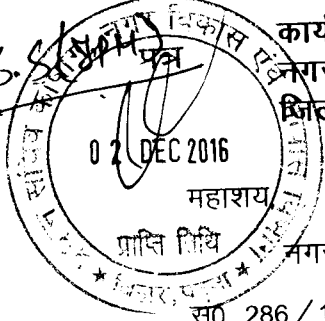
कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/4615/310

दिनांक- 29/11/16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, वीरपुर  
जिला- सुपौल



नगर पंचायत, वीरपुर के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 286/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

-Eo-

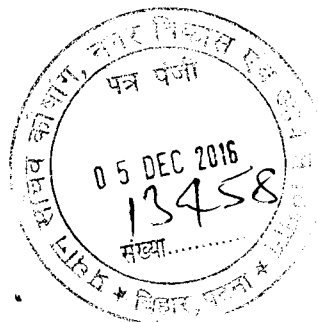
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/4615/310

दिनांक- 29/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सुपौल



वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर निगम मात्र इसका वसूलकर्ता के रूप में कार्य करता है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद में वसूल की गई कुल राशि 506624.00 रु थी। परंतु कार्यालय द्वारा 10 प्रतिशत का वसूली शुल्क काटकर शेष राशि 455961.60 रु सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्न है:-

मद	2013-14	2014-15	2015-16
स्वास्थ्य शेष	72218	97628	83466
शिक्षा शेष	72218	97628	83466
कुल	1,44,436.00	1,95,256.00	1,66,932

**कार्यालय का जवाब:-** सरकार को उपकर की राशि प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः राशि सरकार को प्रेषित किया जाय।

**कण्डिका:-** 7 सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक पर नहीं करने के कारण राजस्व की हानि,

**राशि ₹ 1.09 लाख**

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1920/आर ई आई मुख्य सचिव दिनांक 14.8.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन बिहार के पत्र संख्या 549 दिनांक 13.3.2005 के अनुसार सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती राशि पर 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक पर बन्दोबस्तीधारी के साथ एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि में सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक शुल्क पर नहीं की गई, जिसके कारण राज्य सरकार को 108915.00 रु के राजस्व की हानि हुई।

विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती की राशि			कुल	मुद्रांक शुल्क की राशि @ 3 प्रतिशत
		2013-14	2014-15	2015-16		
1	बस पड़ाव	1203500	608600	815100	2627200	
2	हाट	552000	0	348000	900000	
3	गुदड़ी	0	40300	63000	103300	
कुल					3630500	108915.00 रु

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बस पड़ाव के बन्दोबस्ती की राशियों 1203500.00 रु एवं 608600.00 रु पर देय मुद्रांक शुल्क की राशि 36105.00 रु एवं 18258.00 रु थी, परंतु सिर्फ 100-100 रु का स्टाम्प लिया गया तथा एकरारनामा का कोई शर्त नहीं लिया गया।

कार्यालय का जवाब:- आगे से की जाने वाली बन्दोबस्ती पर स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा किया जायेगा। अतः स्टाम्प शुल्क के रूप में हुई हानि 108915.00 रु की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

**कण्डिका:- 8 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि ₹ 3.65 लाख**

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क 30000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होंने पूर्व में टावर का अधिष्ठापण किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

**लेखा परीक्षा आपत्तियाँ:-**

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में जिसके जमीन/मकान पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित था को नोटिस दिया गया।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 03 मोबाईल टावर अधिष्ठापित था तथा इन कम्पनियों द्वारा इनके

अधिष्ठापण के वर्ष से ही कोई शुल्क नगर पंचायत कार्यालय को नहीं दिया गया एवं कुल मांग राशि 365 लाख रु बकाया के रूप में था।

3. बकाया की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

**कार्यालय का जवाब:-** पूर्व में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार नोटिस दिया गया है। पुनः आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित किया जाय।

**कण्डिका:- 9 दैनिक मजदूरी पर अनियमित भुगतान, राशि 10.95 लाख रु**

रोकड़पाल रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच नगर पंचायत वीरपुर द्वारा दैनिक मजदूरी पर रु0-10,94,852 व्यय की गयी थी जबकि बिहार सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैनिक मजदूरी पर कर्मी को नहीं रखा जाना है। किया गया व्यय अनियमित है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- VII पर संलग्न)

**कार्यालय का जवाब:-**

सफाई कर्मी की कमी होने के कारण एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए कर्मियों को दैनिक मजदूरी पर रखा गया। वर्ष 2014-15 में सफाई कार्य संवेदक को दिया गया था जिसके कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण हटा दिया गया है। आगे पुनः सफाई कार्य हेतु निविदा कराया जायेगा।

अतः सफाई कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाय एवं दैनिक मजदूरी पर कार्य नहीं कराया जाय। भुगतान की गई राशि 1094852.00 रु को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**कण्डिका:- 10 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की राशि का विचलन राशि ₹ 11.89 लाख**

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही व संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक:- 14.11.12 को प्रारंभिक शेष:- 214661.00 रु था तथा दिनांक 14.11.12 को 3000000.00 रु का आवंटन कौशल प्रशिक्षण व स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुआ था, जिसमें से प्रशिक्षण हेतु कुल 1745663.00 रु व्यय किया गया। अतः राशि 1468998.00 रु बचना चाहिए था, परंतु पास बुक में राशि 279487.00 रु (एस बी आई के खाता संख्या-11712632872 में दिनांक-28.12.15 को 258429.80 रु एवं सेंट्रल बैंक के खाता संख्या-2120945328 में दिनांक 06.08.15 21058.30 रु) ही उपलब्ध था। विवरण निम्न है:-

रोकड़ बही की तिथि	राशि
23.03.13	500000
18.04.13	300000
18.04.13	300000
16.08.14	252173
20.08.14	393490
कुल	1745663

इस प्रकार इस योजना के राशि 1189511.00 रु (1468998- 279487) का विचलन कर तेरहवीं व अन्य मदों के योजनाओं में व्यय किया गया। रोकड़ बही में तेरहवीं व अन्य योजना मदों के आवंटन व योजनाओं में व्यय की प्रविष्टियों की गई थी। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में ब्याज की भी प्राप्ति हुई थी।

**कार्यालय का जवाब:-** राशि का समायोजन कर अवशेष राशि विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

अंतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

**कण्डिका:- 11 नगर पंचायत के कार्यालय भवन के निर्माण में अनियमितताएँ**

राज्य सरकार द्वारा नगर विकास विभाग को पत्रांक-1398, दिनांक- 30.03.2007 के माध्यम से नगर पंचायत वीरपुर को प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रु0- 38,50,500 के मानक प्राक्कलन के आधार पर 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में रु0- 28,87,875 के अनुदान की स्वीकृति दी गयी। उक्त राशि तथा पंचायत को नगर विकास विभाग के पत्रांक-160, दिनांक-17.04.2007 के अनुसार बैंक ड्राफ्ट नं0- 090741 दिनांक- 11.04.07 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी। भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2007 में प्रारम्भ हो सका। उक्त योजना के विभागीय क्रियान्वयन हेतु श्री अरुण कुमार राय, कर संग्राहक को अभिकर्ता नियुक्त किया गया। योजना के अंतर्गत श्री राय को कुल रु0- 25,15,000.00 का अग्रिम निम्न प्रकार से दिया गया:-

दिनांक	राशि
1. 30/08/07	15,000.00
2. 24/12/07	2,00,000.00
3. 04/01/08	3,00,000.00
4. 31/01/08	4,50,000.00
5. 29/03/08	3,00,000.00
6. 29/04/08	5,00,000.00
7. 02/08/08	5,00,000.00
8. 31/10/09	2,50,000.00
	<u>25,15,000.00</u>

21,08,2006/-

संचिका में की गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा 21.08.2006/- का मापीपुस्त प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसके विरुद्ध एक भी अभिश्रव अथवा मस्टर रौल समर्पित नहीं किया गया था।

संचिका में दी गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा दिनांक 14.09.08 को वीरपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गयी थी कि दिनांक 18/08/2008 को आये बाढ़ में भवन निर्माण हेतु रखी गयी रु 566600 की सामग्री या तो बह गयी या चुरा ली गयी।

दिनांक 16/06/2012 को संचिका में की गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मापी कराकर शेष कार्य टेण्डर के माध्यम से कराने का निर्णय किया गया।

173  
11/16

इसी बीच नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत के अनुरोध पर सामग्री का मुल्य बढ जाने के कारण पत्रांक 3189 दिनांक 19.06.08 द्वारा रु 50 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की सहमति दी गयी।

प्रशासनिक भवन के शेष कार्य हेतु दिनांक 18/12/2012 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसके अनुसार प्राक्कलन राशि 4394149 थी एवं बी० ओ० क्यू० के अनुसार प्राक्कलित राशि रु 4396380 थी। बी०ओ०क्यू० दर पर निविदा देकर कार्य पूर्ण कराया गया।

यद्यपि बी० ओ० क्यू० के अनुसार प्राक्कलन रु 4396380 का ही था लेकिन भुगतान मापीपुस्त में वर्णित रु 4534799 का किया गया जो कि रु 138419 अधिक था।

आगे यह भी देखा गया कि बी० ओ० क्यू० में दरवाजों एवं खिडकियों के चौखट एवं दरवाजा के लिये रु 327807 का प्राक्धान (item No 11) किया गया था। परन्तु वर्ष 15-16 में नगर पंचायत द्वारा इस कार्य हेतु एक अभिकर्ता को रु 351080 का भुगतान किया गया।

लेखा-परीक्षा टिप्पणी

1 श्री राय द्वारा प्रतिवेदित रु 566600 के सामग्री के बाढ में बह जाने /चोरी हो जाने के मामले में कार्यालय द्वारा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

2. कार्यालय भवन निर्माण में कुल 69.94 लाख रु व्यय किया जा चुका था, विवरण निम्न है:-

1	श्री राय के माध्यम से	2108206 ✓
2	संवेदक के माध्यम से	4534799 ✓
3	दरवाजा खिडकी मद में	351080 ✓
कुल		6994085

इस प्रकार रु 50 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन से भी रु 1994085 का अधिक व्यय किया जा चुका था।

विभाग के पत्रांक 366 दिनांक 21/01/10 के अनुसार योजना की स्वीकृति एवं आवंटन के पश्चात स्थानीय स्तर पर विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि हुई है तो वैसी स्थिति में बढी हुई अंतर राशि जिम्मेवार पदाधिकारी से वसुल की जानी है। परन्तु इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई किया गया या नहीं, से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

3 श्री राय को प्रदान किए गये रु 2515000 के अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था।

4 श्री राय द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मापी की गयी थी अथवा नहीं, इससे अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

5 संवेदक को बी०ओ०क्यू० से रु 138419 का अधिक भुगतान किया गया था।

6. जब बी०ओ०क्यू० में रु 327807 का प्राक्धान खिडकी/दरवाजा हेतु किया गया था, जिसके अनुसार भुगतान भी किया गया था, परन्तु अलग से उस मद में रु 351080 का व्यय वर्ष 2015-16 में किया गया, जिसकी जाँच कराई जाय।

कार्यालय का जवाब:-

दर्ज आपतियों पर कार्रवाई की जायेगी तथा अग्रिम/अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:- अतः पुनरीक्षित प्राक्कलन से अधिक व्यय की गई राशि 1994085.00 रु जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है। अग्रिम का समायोजन/वसूली किया जाय।

**कण्डिका:- 12 जलापूर्ति योजना के कियान्वयन में अनियमितताएँ**

वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- SPUR-PMU/108/ROB-ULBs/2012/70 दिनांक-11.04.12 के तहत स्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/नवनिर्मित कार्यालय भवन के शेष कार्य/फर्नीचर इत्यादि के लिए 3.50 करोड़ रु का आवंटन नगर पंचायत-वीरपुर को दिया गया, जिसमें से Renovation and rehabilitation of water supply scheme including Water treatment plant के लिए 1.10 करोड़ रु की राशि कर्णांकित की गई। परंतु कार्यालय द्वारा इस योजना को तीन भाग में विभक्त कर कार्यान्वित किया गया तथा इन तीनों के लिए दिनांक-26.12.13 को खोले गये निविदा में एक ही संवेदक श्री राजेश कुमार सिंह सफल हुए तथा इन्हें कार्य आवंटित किया गया। विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रु में)	सफल संवेदक का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि (मापी पुस्त. के अनुसार)
1	पी एच ई डी टंकी में आयरन रिमूवल प्लांट लगाने का कार्य	3741100	श्री राजेश कुमार सिंह	20.02.14	22.12.14
2	पानी आपूर्ति हेतु नये पाईप लाईन बिछाने एवं गाड़ने का कार्य	3736600	तथैव	तथैव	12.06.15
3	पानी आपूर्ति हेतु पुराने पाईप लाईन का मरम्मत कार्य	3412400	तथैव	तथैव	22.08.15
कुल		10890100			

**लेखा परीक्षा आपतियाँ:-**

- उपर्युक्त तीनों योजनाएँ विशेष कर क्रम संख्या-2 एवं 3 एक ही प्रकृति के थे। लेकिन कार्यपालक अभियंता से उच्चतर प्राधिकारी से निविदा निष्पादन से बचने हेतु योजना को तीन भाग में विभक्त कर 1.09 करोड़ रु की योजना को कार्यान्वित किया गया।
- योजना संख्या-1 में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाला, जिसमें से दो निविदा समान दर पर दिया गया तथा एक निविदादाता के द्वारा श्रम अनुज्ञप्ति नहीं दिये जाने के कारण इन्हें अयोग्य करार दिया गया। योजना संख्या-2 व 3 में दो निविदादाताओं द्वारा निविदा डाला गया, जिसमें से एक निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि जमा नहीं करने के कारण इन्हें अयोग्य करार दिया गया। इस प्रकार इन

11387

योजनाओं में न्यूनतम तीन निविदा का शर्त पूरा नहीं हुआ तथा योजना संख्या- 2 व 3 में एकल निविदा पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

3. जल की आपूर्ति बहाल की गई या नहीं से संबंधित कोई प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया एवं यदि आपूर्ति बहाल की गई हो तो जल कर अधिरोपण नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
4. दिनांक 26.12.13 को निविदा कार्य संपन्न हुआ परंतु कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया क्योंकि कार्यालय पत्रांक- 105 दिनांक- 12.02.14 के अनुसार निविदा निष्पादन में निम्न दिक्कतें आ रही थी, जिसके निराकरण हेतु कार्यालय द्वारा डूडा, सुपौल तथा नगर पंचायत के सहायक व कनीय अभियंताओं से निम्न सूचनाओं की मांग की गई:-
  1. पी एच ई डी से जल सप्लाई हेतु विस्तृत जानकारी ली गई है अथवा नहीं।
  2. शहर में फ़ैले विस्तृत पुराने नष्ट हुए नल पाईपों का विवरणी पी एच ई डी से लिया गया है अथवा नहीं।
  3. नये नल पाईप से कितनी आबादी लाभान्वित होगी।
  4. नये नल पाईपों को किन-किन वार्डों में लगाये जाने की योजना है।
  5. संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण पी एच ई डी के अभियंता से कराना आवश्यक है या नहीं।

कनीय अभियंता, न0 पं0 वीरपुर द्वारा जवाब दिया गया कि :-

1. पी एच ई डी के कनीय अभियंता के उपस्थिति में ही जल सप्लाई हेतु विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत प्राक्कलन तैयार करवाया गया है
2. पाईपों में जल छोड़ने के उपरांत ही पता चलेगा कि कौन से पाईप क्षतिग्रस्त है।
3. पाईप लाईन बिछाने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी आबादी लाभान्वित होगी।
4. विभाग के विचारोपरांत ही निर्णय लिया जायेगा कि नये पाईप लाईन को कहाँ गाड़ना है ?
5. कार्यालय के आदेश में ही पी एच ई डी के कनीय अभियंता से कार्य का पर्यवेक्षण कराने एवं प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

उपर्युक्त जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा विस्तृत सर्वे किये बिना ही प्राक्कलन तैयार कराया गया तथा निविदा का कार्य भी संपन्न कर लिया गया क्योंकि कार्यालय को यह पता ही नहीं है कि कहाँ नये पाईप लाईन को गाड़ना है तथा कहाँ- कहाँ पुराना पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है एवं कितनी आबादी इससे लाभान्वित होगी। उल्लेखनीय है कि ये विसंगतियां ठेकेदार को दिनांक-20.02.14 को कार्यादेश निर्गत करने के बाद भी विद्यमान थी जिसे ठेकेदार द्वारा दिनांक- 10.11.14 को आवेदन दिया गया कि योजना संख्या- 2 में किन स्थानों पर कार्य कराना है, उसकी सूची नहीं दी गई है।

5 इन योजनाओं को कार्यादेश के अनुसार तीन माह अर्थात 20.05.14 तक पूर्ण हो जाना था, परंतु उपरोक्त विसंगतियों के कारण कार्य को पूर्ण होने में 7 माह से 15 माह तक विलंब हुआ।

कार्यालय का जवाब:- भौगोलिक स्थिति के कारण तीन अलग- अलग प्राक्कलन तैयार कर बोर्ड के बैठक में रखा गया। बोर्ड के निर्णयानुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया। पानी की आपूर्ति की गई है। जल कर अधिरोपण किया जायेगा।

अतः भविष्य में एक ही प्रकृति की योजनाओं को विभक्त कर कार्यान्वयन कराने से बचा जाए एवं पी0 एच0 ई0 डी0 से नगर पंचायत द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति की योजना पर सहमति प्राप्त कर ली जाय एवं अन्य संबंधित आपत्तियों का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।



कण्डिका:-13

योजना सं०-16/15-16, ईदगाह से मदरसा चॉक तक सड़क निर्माण

प्राक्कलित राशि-	2.56,100.00	
तकनीकी स्वीकृति-	22.07.15	
कार्यदेश-22.08.15		
अभिकर्ता को भुगतान -	22.08.15	7500
	21.09.15	153500
	09.05.16	56764
		<u>217764</u>
वैट एवं रॉयल्टी की कटौती-	16506	
		<u>234270</u>

मापीपुस्त में अंतिम राशि/तिथि - 234230, दि०-31.08.15

अभिभ्रव का विवरण:-

26.06.15, M/S Bijiya Trading Company	59,800
बालु ढुलाई हस्तलिखित सादा कागज अभिभ्रव 7.76 M <sup>3</sup>	18,055
स्टोनचिप्स ढुलाई -तथैव-15.53 M <sup>3</sup>	35,780
मेटल ढुलाई -तथैव-10.35 M <sup>3</sup>	23,845
बालु ढुलाई -तथैव-6.90 M <sup>3</sup>	1,141
स्थानीय बालु -तथैव-254.00 M <sup>3</sup>	49,677
	<u>188298</u>

मजदूर नामावली

दिनांक अंकित नहीं 45972

कुल= मजदूर नामावली+ अभिभ्रव= 45972+ 188298= 234270

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ:-

1. प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि दर्ज नहीं थी।
  2. मजदूर नामावली पर किस तिथि से कब तक मजदूरों ने कार्य किया था, अंकित नहीं था।
  3. अभिलेख/मापीपुस्त के अनुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस (234230 का 1%) 2342 की कटौती नहीं की गयी थी।
  4. प्राक्कलन में Contractor Profit 10% नहीं घटाया था।
  5. प्राक्कलन तथा मापीपुस्त में ढुलाई का प्राक्कलन नहीं किया गया था जबकि संचिका में सामग्री ढुलाई का अभिभ्रव संलग्न था।
  6. अभिभ्रव के अनुसार सामग्री का क्रय तकनीकी स्वीकृति तथा कार्यदेश के पूर्व ही किया जा चुका था।
- कार्यालय का जवाब:- आपति के आलोक में जाँच के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

1/36/04

अतः उपर्युक्त आपतियों का निराकरण किये जाने तक योजना पर व्यय राशि 234270.00 रु को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**कण्डिका:-14**

योजना सं०-08/14-15, कार्यालय भवन का चार दिवारी का निर्माण।

प्राक्कलित राशि-	123500.00	
तकनीकी स्वीकृति-	14.07.14	
कार्यादेश-167, दिनांक-04.06.15 कार्यपालक पदाधिकारी		
मापीपुस्त में अंतिम मापी/तिथि -	112255,	दि०-20.06.15
अभिकर्ता को भुगतान -	18.06.15	7500
	11.07.15	98853
		<u>106353</u>
वैट एवं रॉयल्टी की कटौती-		5902
		<u>112255</u>

**अभिभ्रव का विवरण:-**

R.C.S. Bricks Industry, 25.06.15, 7894 Nos	39,140
Carries of bricks gLrfyf[kr dkxt	4,613
Chips, M/S Bijiya Trading Company 28.06.15, 1.48 M <sup>3</sup>	751
Carriage of chips. 1.48 M <sup>3</sup> , 28.06.15	3,410
M/S Bijiya Trading Company, 28.06.15 Sand per M <sup>3</sup>	2,729
Carriage of Sand per M <sup>3</sup>	25,594
Cement 63 Bag, 28.06.15	20,538
Snow bean, 02.07.15 20 kg	966
	<u>97,741</u>

**मजदुर नामावली**

दिनांक अंकित नहीं

-वही-	5020
-वही-	2510
-वही-	948
	<u>8648</u>

कुल मजदुर नामावली+ अभिभ्रव= 97741+ 17126=114867

**लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ:-**

1. मापीपुस्त के अनुसार कार्य 20.06.15 को पूर्ण कर लिया गया था किन्तु अभिभ्रव के तिथि के अनुसार 28.06.15 को चिप्स, बालु का क्रय/दुलाई किया गया था। अतः सामग्री का क्रय/प्रयोग योजना में संदिग्ध प्रतीत होता है।
2. मजदूर नामावली में मजदूरों की उपस्थिति तिथि दर्ज नहीं थी।
3. 1 प्रतिशत श्रम सेस ₹ 1122.00 (112255 X 1%) की कटौती नहीं की गयी थी।
4. वैट एवं रॉयल्टी कटौती की राशि ₹ 3902 का जमा सरकार के राजस्व शीर्ष में दिखाया जाय।
5. संचिका में संलग्न कागजात से प्रशासनिक तिथि स्पष्ट नहीं हो पाया था।

6. मापीपुस्त तथा प्राक्कलन में ढुलाई का ब्रेक-अप दर्ज नहीं था जबकि संचिका में अभिश्रव संलग्न था।  
7. कॅन्ट्रेक्टर प्रॉफीट प्राक्कलन में नहीं घटाया गया था।

**कार्यालय का जवाब:-** आपति के आलोक में जाँच के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त आपतियों का निराकरण किये जाने तक योजना पर व्यय राशि 112255.00 रु को आपति के अधीन रखा जाता है।

### भाग-III

**टिप्पणी:- 01 लेखापाल रोकड़ बही में त्रुटियाँ**

1. रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को दर्ज अंतशेष की राशि 27693185.00 रु था, जबकि गणना करने के उपरांत वास्तविक अंतशेष 27107605.61 रु होगा, अर्थात् अंतशेष की राशि को 585570.30 से अधिक कर दिया गया था। यह त्रुटि प्रारंभिक शेष के रूप में दिनांक 01.04.15 को 502844.00 रु एवं दिनांक 30.04.15 को 82726.30 रु अधिक दर्ज करने के कारण था।

रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को दर्ज अंतशेष की राशि:-27693185.61

(-)502844.00

(-)82726.30

वास्तविक अंतशेष की राशि दिनांक 31.03.16 को = 27107615.61

एक ही रोकड़बही में कई मदों यथा योजनाएँ, स्वयं स्रोत, अन्य मद आदि से प्राप्त आय का लेखांकन किया गया था, तथा विभिन्न योजनाओं/गैर योजनाओं मद में व्यय किया गया था। सभी मदों का सहायक रोकड़बही संधारित नहीं किया गया था।

2. रोकड़बही के व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था।  
3. वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।  
4. रोकड़बही में अधिकांश व्यय के बारे में यह स्पष्ट करना मुश्किल था कि किस मद में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अव्यवहृत पड़ी थी तथा प्राप्त राशि जिस मद एवं जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं।

**कार्यालय का जवाब:-** रोकड़ बही में दर्ज अंतशेष की राशि को सुधार कर लिया जायेगा एवं अन्य आवश्यक त्रुटियों को सुधार कर लिया जायेगा।

अतः इंगित त्रुटियों को सुधार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

**टिप्पणी:-2 रोकड़बही/पासबुक में कमियाँ**

रोकड़बही एवं पासबुक के जाँच के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:-

1	कोषागार पासबुक		
a	Ch No. 105755 25.06.14	1,53,767.00	पेमेंट पासबुक में इंद्राज नहीं है।
b	05.09.14	4,32,703	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है
c	Ch No. 73053 06.11.15	रोकड़ बही में 46450.00 है लेकिन पासबुक में 52784 है।	
d	Ch No. 73082 04.02.16	3,15,840.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।	
2	P.N.B. A/C No.-2489000100078928		
a	Ch No.- 6804 05.02.16	24,000.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है। लेकिन पासबुक है।	
b	Ch No.- 6805 12.02.16	4,56,354.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है। लेकिन पासबुक है।	
c	छमाही ब्याज जो बैंक से प्राप्त होते हैं रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।		
3	P.N.B. A/C No.-2489000100078928		
a	20.03.14	1,66,525.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।
b	26.07.14	3,09,217.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।
c	16.08.14	40,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।
d	18.08.14	33,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।
e	18.08.15	99,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है
f	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
4.	P.N.B. A/C No.-2489000100075897		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
5.	C.B.I. A/C No.-2120945328		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
6	S.B.I. A/C No.- 11712632872		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
7	C.B.I. A/C No.-2121022660		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
8	P.N.B. A/C No.-2489000100075903		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
9	S.B.I. A/C No.- 11712588286		
a	01.04.13 - 01.10.13 तक बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं है।		
b	29.01.16 - 31.03.16 तक बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं है।		
10	C.B.I. A/C No.-3143570556		
a	16.07.15 - 31.03.16 का बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं है।		

अंकेक्षण टिप्पणी

1. S.B.I. CA A/C No.- 11712588286 तथा C.B.I. CA A/C No.- 3143570556 बैंक पासबुक नहीं उपलब्ध कराया गया।

LEE  
1/13/3

2. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

3. उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अंकेक्षण दल को अवगत करायें।

कार्यालय का जवाब:- उपर्युक्त त्रुटियों को सुधार कर लिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

**टिप्पणी:- 03**

नगर पंचायत वीरपुर में अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। रोकड़पाल के रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि कई कर्मचारियों को 2012-13 से 2015-16 के बीच रू०- 13,73,935 अग्रिम दिया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VIII पर संलग्न)

कार्यालय का जवाब:- कुछ अग्रिमों का समायोजन किया गया है एवं अन्य लंबित अग्रिमों का समायोजन किया जायेगा।

अतः अग्रिम के समायोजन की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

—हस्ता०—

सुबोध प्रसाद

(स०ले०प०अ०)

—अनुमोदित—

उप महालेखाकार (एस० एस० 1)

—सह—

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

65  
132

परिषिष्ट- I

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सूची की विवरणी

(प्रतिवेदन के भाग-1 के कड़िका संख्या- 3 से संदर्भित)

क्रम सं०	अभिलेखों का नाम
1.	लेखापाल रोकड बही व पास बुक
2.	टमिश्रव
3.	योजना अभिलेख
4.	सैरात संचिकाएँ
5.	विविध रसीद व इसका भंडार पंजी
6.	क्रय से संबंधित संचिका (आषिक)
7.	संचार मीनारों से संबंधित माँग एवं वसूली विवरणी
8.	भवन करों (हॉल्डिंग्स टैक्स) का माँग एवं संग्रहण विवरणी
9.	योजनाओं से संबंधित विवरणी

no

131

परिषिष्ट-II

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेखों की सूची की विवरणी

(प्रतिवेदन के भाग-1 के कंडिका संख्या- 3 से संदर्भित)

क्रम सं०	अभिलेखों का नाम
1.	दिज्ञापन का माँग एवं संग्रहण (लेखा) पंजी
3.	ऋण विनियोग पंजी
5.	निबंधित वास्तुविदों की पंजी
6.	चल सम्पतियों से संबंधित पंजी/भंडार लेखा
7.	विधि पंजी
8.	सेवानिवृत्त/ मृत कर्मियों के दावे के विवरण से संबंधित पंजी
10.	मदवार आय व व्यय का वार्षिक संवरण
12.	प्राप्तियों व व्यय का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी
13.	जमा पंजी व अग्रिम पंजी
14.	लेखापरीक्षा पंजी
15.	सरकारी प्रतिभूतियों की पंजी
16.	संपत्ति पंजी
17.	किराया पंजी
18.	जमाबंदी पंजी
19.	लीजधारियों की पंजी
22.	ठास अपषिष्ट प्रबंधन से संबंधित पंजी
23.	ह्रास निधि पंजी (Depreciation fund register)
25.	वाहनों का लॉगबुक तथा संबंधित अभिलेख
27.	दुकान किराया की पंजी एवं एकरारनामा
29.	सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
30.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
31.	नक्शा पंजी
33.	संधारित किये गये अभिलेखों की सूची
34.	बजट

10/11/14

63  
130

परिशिष्ट-- III

लेखा परीक्षा परिणाम

प्रतिवेदन के भाग- I कंडिका सं. 9 से संदर्भित

क्र.सं.	कंडिका सं. (II ख)	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि
1	1			1774725
2	2		326929	
3	3		113019	
4	7		108915	
5	9			1094852
6	11		1994085	
7	13			234270
8	14			112255
	कुल		2542948	3216102



परिशिष्ट- IV			
नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान का विवरण (प्रतिवेदन के भाग-1 के कड़िका संख्या- 10 से संदर्भित)			
वर्ष 2013-14			
प्राप्ति तिथि	विवरण	पत्रांक / दिनांक	राशि
10.05.13	तेरहवीं वित्त आयोग	—	980889 191000
31.07.13	पिछडा क्षेत्र अनुदान	—	702879
08.08.13	तेरहवीं वित्त आयोग	12 / 19.07.13	1102933
18.09.13	कबीर अत्येष्टि	—	18000 16500
24.10.13	सामाजिक सुरक्षा पेशन	दर्ज नहीं	938314
06.12.13	पिछडा क्षेत्र अनुदान	—	15890
09.12.13	कबीर अत्येष्टि	—	112500 226500
19.12.13	पारिवारिक लाभ	—	5000
08.01.14	सामाजिक सुरक्षा पेशन	—	248904
30.01.14	पिछडा क्षेत्र अनुदान	—	1195848 26928
05.03.14	पथ निर्माण हेतु	—	1973913 1326087
14.03.14	सामाजिक सुरक्षा पेशन	—	295267
20.03.14	पेशा कर मद में प्राप्त आवंटन	42 / 26.09.13	343883
21.03.14	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	102 / 15.03.14	7201162
कुल			<b>16922397</b>
2014-15			
27.05.14	तेरहवीं वित्त आयोग	—	1057847
30.08.14	पेशा कर	14 / 16.06.14	432703
19.08.14	सामाजिक सुरक्षा पेशन	—	175221
19.08.14	तेरहवीं वित्त आयोग	—	1057847
27.09.14	कबीर अत्येष्टि	507 / 22.09.14	138000 48000
17.10.14	तेरहवीं वित्त आयोग	—	1083131
10.11.14	पारिवारिक लाभ	391 / 31.07.14	20000 110000 10000
17.11.14	सामाजिक सुरक्षा पेशन	—	480120
29.12.14	प्रतिनिधि भता	—	130800
02.12.14	सामाजिक सुरक्षा पेशन	—	72500
13.01.15	ई गवर्नेस योजना के तहत तीन टेबलेट क्रय हेतु	98 / 09.01.15	150000
18.02.15	सामाजिक सुरक्षा पेशन	—	858400
16.03.15	ई गवर्नेस योजना के तहत महिला वार्ड पार्श्वों के लिए	—	150000

mda